



झारखण्ड सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिति
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

स्वास्थ्य सुधार में झारखंड में बेहतर काम हो रहा है : अश्विनी कुमार चौबे

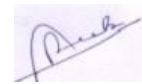
रांची: केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) अश्विनी कुमार चौबे ने झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं में हो रहे सुधार की प्रशंसा करते हुए कहा है कि राज्य में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए बेहतर काम हुआ है वहीं 2014 की तुलना में यहां संस्थागत प्रसव का अनुपात 61.90 प्रतिशत से बढ़कर 2017 में 82 प्रतिशत पर पहुंच गया है। श्री चौबे शुक्रवार 25 मई, 2018 को मोरहाबादी स्थित राजकीय अतिथिशाला में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। पत्रकारों द्वारा पूछने पर उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को जेनरिक दवाई लिखने का निर्देश दिया गया है जिसका कड़ाई से पालन करवाया जायेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग के अलावा झारखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) द्वारा सुदूर ग्रामीण इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। श्री अश्विनी चौबे ने कहा कि पिछले सालों में झारखंड मातृ मृत्यु दर सुधारने वाले राज्यों में तीसरे नंबर पर आ गया है और यहां 2017 में मातृ मृत्यु दर प्रति लाख में 208 दर्ज किया गया है जो राष्ट्रीय औसत 167 से कुछ कम है। उन्होंने कहा कि कल देर रात तक चली बैठक में अधिकारियों ने बताया कि झारखंड में मृत्यु दरों में सुधार के लिए 2020 और 2030 का रोडमैप तैयार किया गया है जिसमें यह योजना भी बनायी गयी है कि इन मृत्यु दरों को कैसे राष्ट्रीय मानक के बराबर लाया जाये। उन्होंने इस रोडमैप की प्रशंसा की।

संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि मोदीजी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 2020 तक टीकाकरण 90 प्रतिशत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है और मुझे इस बात की खुशी है कि जहां 2014 में झारखंड में 61.90 प्रतिशत टीकाकरण हो रहा था, 2017 में 95 प्रतिशत बच्चों का टीकाकरण किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि रांची के 330 में से 308 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव की व्यवस्था की गयी है। झारखंड के इन कार्यों को देखते हुए केंद्र सरकार यहां के प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन प्लान (पीआईपी) में अधिकांश सहयोग कर रही है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नैशनल डायलिसिस प्रोग्राम के तहत देश के अधिकांश राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सरकारी के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी जांच करवाने की सुविधा दी गयी है। उन्होंने कहा कि अमृत योजना के तहत देशभर में 400 किस्म की

दवाईयां एमआरपी दर से 70 प्रतिशत कम मूल्य पर लोगों को प्रदान की जा रही है। श्री चौबे ने बताया कि देशभर में 3200 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जन औषधि केंद्र शुरू किये जायेंगे जिसमें लोगों को जेनरिक दवाई मिलेगी और इन केंद्रों में लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

केंद्रीय मंत्री श्री चौबे ने बताया कि प्रधानमंत्री की पहल पर समेकित स्वास्थ्य नीति बनायी गयी है जिसके तहत आयुष मंत्रालय और योग केंद्र संचालित किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे केंद्र देश भर में शुरू किये जायेंगे। श्री चौबे ने बताया कि देश भर में 72 मेडिकल कॉलेज संचालित किये जा रहे हैं जिसमें से 25 पूर्ण रूप से तैयार मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी सुविधा दी जा रही है। उन्होंने बताया कि रांची के रिम्स और धनबाद स्थित पीएमसीएच में ये सुविधा यहां के लोगों को दी जायेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्वास्थ्य उप केंद्रों को वेलनेस सेंटर में बदला जायेगा। श्री चौबे ने पत्रकारों को बताया कि देशभर में 1.5 लाख स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं जिसमें 12 तरह की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। श्री चौबे ने कहा कि हर राज्य में 15 हजार वेलनेस सेंटर शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है वहीं झारखंड में करीब 711 ऐसे सेंटर शुरू किये जायेंगे। अगले महीने ऐसे कई केंद्रों का उद्घाटन किया जायेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत भारत के 40 प्रतिशत लोगों का बीमा करवाया जायेगा जिसमें अनुमान है कि 10 करोड़ परिवारों के 50-55 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि मोदी केयर योजना के तहत इन परिवारों का 5 लाख रुपये का इंश्योरेंस करवाया जायेगा। प्रधानमंत्री खुद महीने में दो बार इस योजना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। श्री चौबे ने बताया कि अगले कुछ महीनों में सभी संसदीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जायेगा। वहीं आयुष्मान भारत के तहत 1352 तहत की जांच और सर्जरी का शुल्क तय किया गया है। इस संवाददाता सम्मेलन में आईईसी नोडल पदाधिकारी डॉ पुष्पा मारिया बेक के अलावा अन्य कार्यक्रम पदाधिकारी और रिम्स निदेशक उपस्थित थे।



नोडल ऑफिसर
आई0 ई0 सी0 कोषांग